भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 192

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

आर्थिक मंदी का प्रभाव

192. श्री राहुल रमेश शेवले:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की राय है कि वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत जैसी उभरती कुछ बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसी आर्थिक मंदी के वृद्धि दर और आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे, तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में वृद्धि दर में तेजी लाने और आम आदमी की आजीविका के संरक्षण हेतु आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक-अक्तूबर 2019 यह बताता है कि पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है। यह बताता है कि "उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह मंदी और अधिक है जिनमें ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और रूस शामिल हैं, साथ ही साथ कुछ अर्थव्यवस्थाएं वृहत आर्थिक और वित्तीय दबाव से गुजर रही है"। वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी विकास दर विश्व की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तर पर थी। आईएमएफ द्वारा जारी विभिन्न देशों की वृद्धि दर को अनुबंध पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): इस विषय पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार इस बात से अवगत है कि वैश्विक आर्थिक मंदी किसी देश की अर्थव्यवस्था को इसके निर्यात वृद्धि में कमी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में कमी करके प्रभावित करती है। पिछले दो वर्षों में, भारत की निर्यात वृद्धि संतुलित रही है और तदनुसार सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। दूसरी तरफ, एफडीआई नीति में लगातार उदारीकरण के कारण भारत में एफडीआई के अंतर्वाह में वृद्धि हो रही है।

(ड.) सरकार आर्थिक विकास को बढ़ाने और लोगों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। जीडीपी विकास में मंदी को देखते हुए सरकार द्वारा लगातार कई कदम उठाए गए हैं: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में अधिक उदारीकरण, आधार कॉर्पोरेट कर में 30 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक की कमी, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार संस्थाओं में विलय और बाजार में नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये डालना, विद्युत वाहनों की खरीद पर लिए गए ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर

कटौती और जीएसटी परिषद् से विद्युत वाहनों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना, आवासीय क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदमों की घोषणा की गई है जिनमें किफायती आवास के लिए ईसीबी दिशा-निर्देशों में छूट शामिल है।

निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए एमईआईएस को विस्थापित करके निर्यात को बढ़ाने के लिए करों और शुल्कों की अदायगी के लिए योजना का विस्तार करना, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रानिक धनवापसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) के द्वारा एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में विस्तार निर्यात साख के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संशोधित मानदंड। केंद्रीय बजट 2019-20 में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन देते हुए आगामी 5 वर्षों में अवसंरचना और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के पुनर्गठन के द्वारा 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। सतत् रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए परंपरागत उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभप्रद एवं समर्थ बनाने के लिए अपग्रेडेशन एंड रिजनरेशन ऑफ ट्रेडीशनल इण्डस्ट्रीज (एसएफयूआरटीआई) हेतु निधि स्कीम शुरू की गई है ताकि समूह आधारित विकास किया जा सके। सरकार ने सभी किसानों को कैश अंतरण स्कीम "पीएम-किसान" के तहत 6000/- रुपये प्रति वर्ष आय की सहायता का विस्तार किया है, जो कि पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम भूमिधारक किसान तक ही सीमित थी।

अनुबंध

तालिका 1.1. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूर्वानुमान की समीक्षा

(प्रतिशत परिवर्तन, जब तक नोट न किया जाए)

		पूर्वानुमान	
	2018	2019	2020
वर्ल्ड आउटपुट	**3.6**	**3.0**	**3.4**
संयुक्त राज्य	2.9	2.4	2.1
जर्मनी	1.5	0.5	1.2
फ्रांस	1.7	1.2	1.3
इटली	0.9	0.0	0.5
स्पेन	2.6	2.2	1.8
जापान	0.8	0.9	0.5
यूनाईटेड किंगडम	1.4	1.2	1.4
कनाडा	1.9	1.5	1.8
चीन	6.6	6.1	5.8
भारत	6.8	6.1	7.0
रूस	2.3	1.1	1.9
ब्राजील	1.1	0.9	2.0
मैक्सिको	2.0	0.4	1.3
सऊदी अरब	2.4	0.2	2.2
नाईजीरिया	1.9	2.3	2.5
दक्षिण अफ्रीका	0.8	0.7	1.1

*****